जयपुर रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस से खेती-किसानों का नया रोडमैप

तिलहन-दलहन में आत्मनिर्भरता, फार्मर आईडी, प्राकृतिक खेती और राज्यों के नवाचार पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणाएं

हर राज्य का अलग कृषि रोडमैप बनाने के लिए रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस की नई व्यवस्था शुरू की है- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

जयपुर (विराट वैभव)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जयपुर में आयोजित रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस के बाद बताया कि अब पूरे देश को विभिन्न एग्रो-क्लाइमेटिक जोनों में बाँटकर हर राज्य के लिए अलग कृषि रोडमैप बनाया जाएगा। सभी किसानों को फार्मर आईडी से जोड़कर खाद, बीज, फसल बीमा और मुआवजा वितरण की पूरी प्रणाली को पारदर्शी और लक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के अंतर्गत 2024-25 में 429.89 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन और उत्पादकता में हुई बढ़ोतरी को और आगे बढ़ाते हुए तिलहन का क्षेत्र 29 मिलियन हेक्टेयर से 33 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन 39.2 मिलियन टन से 69.7 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है जबकि दलहन मिशन के तहत बीज उत्पादन, दाल मिलों की स्थापना, नई बीज किस्मों को सीड चेन में लाने तथा इच्छुक किसानों से 100 प्रतिशत खरीद के माध्यम से देश को दालों में भी मजबूत आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाएगा।

राज्यवार कृषि रोडमैप और रीजनल कॉन्फ्रेंस

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें ढ्ढष्टक्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, स्नक्करूह्र, नेफेड, हृष्टष्टस्न और बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली सभी संस्थाएं एक मंच पर आई हैं जबकि पहले खरीफ और रबी के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें समयाभाव से विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि अब देश को पाँच एग्रो-क्लाइमेटिक जोनों में बाँटकर पाँच रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएँगी जिनमें हर राज्य की जलवायु, मिट्टी, पानी और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अलग कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार यह तय होगा कि किस इलाके में कौन-सी फसल, कौन-सी किस्म और कौन-सी कृषि पद्धति सर्वोत्तम होगी।

फार्मर आईडी: खाद, बीज, बीमा और मुआवजा की रीढ़

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सभी राज्यों में फार्मर आईडी बनाने का काम तेज गति से चल रहा है और विश्वास जताया कि लगभग तीन महीने में सभी किसानों की एकीकृत पहचान तैयार हो जाएगी जिससे किसान को हर योजना का लाभ सीधे और सटीक रूप से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फार्मर आईडी के आधार पर खाद वितरण का जो मॉडल लागू है, उसी तर्ज पर पूरे देश में व्यवस्था की जाएगी जिसमें किसान को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसकी जमीन और फसल के अनुसार आवश्यक मात्रा में खाद मिलेगा, नकली या ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सकेगी और टेनेंट/बटाईदार किसानों को भी मालिक की स्वीकृति के आधार पर फार्मर आईडी से खाद व अन्य सुविधाएँ मिलेंगी। यही आईडी आगे फसल बीमा, फसल-क्षति मुआवजा और अन्य लाभों का भी आधार बनेगी।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन: रिकॉर्ड प्रगति और आगे की उड़ान

श्री शिवराज सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के अंतर्गत 2024-25 में तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर 429.89 लाख टन तक पहुँच गया है, जो 2023-24 में 396.69 लाख टन था। उन्होंने कहा कि उत्पादकता 2023-24 के 1314 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 1412 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है जो किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह संदेश देती है कि सही नीति, बीज, तकनीक और प्रोत्साहन से देश तिलहन में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2025-26 में 1076 वैल्यू चेन क्लस्टरों के माध्यम से 13.35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को तिलहन के अंतर्गत लाया गया है, 60 बीज केंद्र स्थापित किए गए हैं, 50 बीज भंडारण इकाइयों को मंजूरी दी गई है और 400 तेल मिलें स्थापित हो चुकी हैं जबकि कुल 800 तेल मिलें स्थापित करने का लक्ष्य है ताकि उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और बाजार तक पूरी श्रृंखला मजबूत हो।

तिलहन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य: क्षेत्र, उत्पादकता और उत्पादन

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 10,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों को तकनीक, बीज, सिंचाई, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल सके। उन्होंने बताया कि लक्ष्य यह है कि तिलहन का क्षेत्र 29 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर किया जाए, उत्पादकता 1353 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जाए और कुल उत्पादन 39.2 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन मैट्रिक टन तक ले जाया जाए ताकि खाद्य तेलों में आयात पर निर्भरता में निर्णायक कमी लाई जा सके और किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों से अधिक आय मिले।

दलहन मिशन: बीज, दाल मिलें, नई किस्में और 100% खरीद

श्री शिवराज सिंह ने बताया कि दलहन मिशन के तहत सभी राज्यों को बीज उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने के लिए कहा गया है ताकि दालों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज किसान के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अरहर, उड़द, मसूर आदि दालों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल सहायता दी जाएगी- तुर में 4500 रुपये प्रति क्विंटल, तुर-उड़द में 2000 रुपये प्रति क्विंटल और चना में 1800 रुपये प्रति क्विंटल की मदद दी जा रही है ताकि किसान अच्छे बीज तैयार करने के लिए प्रेरित हों। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को सब्सिडी पर बीज वितरण के लिए भी राज्यवार लक्ष्य तय किए गए हैं- मध्य प्रदेश के लिए 3,10,870 क्विंटल, राजस्थान के लिए 2,45,000 क्विंटल, महाराष्ट्र के लिए 87,500 क्विंटल और गुजरात के लिए 40,000 क्विंटल दलहन बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने कहा कि नई दलहन किस्मों को शीघ्रता से सीड चेन में लाने पर विशेष जोर दिया गया है; राजस्थान में 79, गुजरात में 58, मध्य प्रदेश में 63 और महाराष्ट्र में 58 नई दाल किस्मों की पहचान और उपयोग पर काम हो रहा है।

दलहन उत्पादन के हॉटस्पॉट, दाल मिलों का नेटवर्क और राज्यों के लिए वित्तीय प्रावधान

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि दलहन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात मिलकर देश के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं और इन राज्यों के कई जिले- जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, राजस्थान में झालावाड़ व टोंक, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और गुजरात में जूनागढ़ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें मॉडल जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में दलहन उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, वहाँ की समीक्षा कर उत्पादकता में वृद्धि के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि दलहन प्रोसेसिंग को गति देने के लिए दाल मिलों का बड़ा नेटवर्क विकसित किया जा रहा है; मध्य प्रदेश में 55, महाराष्ट्र में 34, गुजरात में 28, राजस्थान में 30 और गोवा में 5 दाल मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ताकि उत्पादन के साथ-साथ प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन भी हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश को 344 करोड़ रुपये, राजस्थान को 312 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 166 करोड़ रुपये और गुजरात को 31 करोड़ रुपये दलहन मिशन के तहत उपलब्ध कराए जाएँगे और तुर, उड़द, मसूर जैसी दालों में इच्छुक किसानों की 100 प्रतिशत उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान रखा गया है जिससे किसानों को गेहूँ-चावल की तरह दालों में भी पूर्ण सुरक्षा का भरोसा मिल सके।

विकसित कृषि संकल्प, इंटीग्रेटेड-प्राकृतिक खेती और नकली खाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान अब राज्यों के कृषि-मौसम और फसल चक्र के अनुसार चलाया जाएगा और लगभग 16,000 वैज्ञानिक, ढ्ढष्टक्र संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र सीधे किसानों के बीच जाकर 'लैब टू लैंड' के सिद्धांत पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छोटी जोतों पर आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल- अनाज के साथ फल, फूल, सब्जियाँ, औषधीय खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बकरी पालन और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा और प्राकृतिक खेती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने, मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के जरिए किसानों को प्रीमियम बाजार दिलाने पर सहमति बनी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि नकली खाद और नकली कीटनाशकों के खिलाफ पहले भी बड़े अभियान चलाए गए हैं, कई फैक्ट्रियाँ सील की गई हैं, लेकिन अब एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे माल के निकलने से लेकर किसान तक पहुँचने तक पूरी चेन पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि 1968 के पुराने कानून में केवल मामूली जुर्माने की व्यवस्था है, इसलिए नकली बीज, खाद और पेस्टिसाइड के खिलाफ कड़े कानून लाने पर व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है और अगले सत्र में संशोधन/नया कानून लाकर दोषियों को कठोर सजा देने की दिशा में कदम उठाए जाएँगे।

फसल-क्षति, युद्ध का असर, ञ्जह्रक्क (आलू-प्याज-टमाटर) और लचीली फंडिंग

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर सेटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग से फसल-क्षति का वैज्ञानिक आकलन करने पर काम हो रहा है ताकि राज्य सरकारें क्षति का आकलन कर आरबीसी 6(4) के तहत स्ठक्रस्न से राहत दें और साथ-साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फार्मर आईडी के आधार पर रिकॉर्ड समय में बीमा राशि किसानों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों का असर खाद और कृषि इनपुट पर पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि भारत विशेषकर किसानों पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़े और फिलहाल देश में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पर्याप्त खाद भंडार मौजूद है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों में अधिक उत्पादन पर कीमत गिरने और किसानों को डिस्ट्रेस सेल करने की स्थिति से बचाने के लिए राज्य सरकारें अपनी संस्थाओं के माध्यम से किसानों से सीधे खरीद कर बड़े शहरों तक आपूर्ति करेंगी और इस प्रक्रिया में गाँव से शहर तक ट्रांसपोर्ट और भंडारण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी ताकि किसान को ठीक दाम और उपभोक्ता को वाजिब कीमत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि हर राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार योजनाओं में लचीलापन मिले- जिसे ड्रिप सिंचाई की जरूरत है, उसे उसी मद में, जिसे मैकेनाइजेशन या प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, उसे उसी मद में अधिक राशि दी जाएगी ताकि संसाधन वहीं लगें जहां उनकी वास्तविक जरूरत हो।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम

मानसिक स्वास्थ्य के लिए राज–ममता कार्यक्रम का शुभारंभ, एसएमएस में अत्याधुनिक डर्मेटोलॉजी संस्थान प्रारंभ, चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया संवाद

जयपुर, (विराट वैभव)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत एवं सुगम बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मंगलवार को चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर द्वारा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक डर्मेटोलॉजी संस्थान एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार राज–ममता कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। साथ ही, उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विषयों पर संवाद एवं समीक्षा भी की।

चिकित्सा मंत्री ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में राज-ममता (राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटयोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल) कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही, उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन समीक्षा के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग एप एवं आउटरीच एप को भी लांच किया।

एसएमएस में बनेगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सीलेंस सेंटर

खींवसर ने कहा कि बढ़ते तनाव के दौर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं बेहतर उपचार सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने अभिनव पहल करते हुए राज–ममता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत एसएमएस अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे तथा मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिक्षण संस्थानों में तनाव प्रबंधन कार्यशाला एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे। विद्यालयों में मानसिक परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

निजी अस्पतालों की तुलना में कम लागत में होगा त्वचा रोग इलाज

खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि डर्मेटोलॉजी संस्थान में स्थापित अत्याधुनिक मशीनें, विशेष रूप से एआई (ढ्ढ) आधारित तकनीक, त्वचा रोगों के निदान और उपचार को अधिक सटीक, प्रभावी और आधुनिक बनाएंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से आमजन को अब निजी अस्पतालों की तुलना में कम लागत पर उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का स्तर और अधिक उन्नत होगा।

एक पद पर नहीं रहेंगे दो कार्मिक

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग ने राज हैल्थ पोर्टल के माध्यम से आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ को नियुक्ति प्रदान की गयी है। प्रदेशभर में फर्स्ट रेफरल यूनिट्स एवं ट्रोमा सेंटर को फंक्शनल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनूहोंने सभी संयुक्त निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों में ओपीडी-आईपीडी भार के आधार पर चिकित्सकों एवं स्टाफ के रिक्त पदों का असेसमेंट करने के भी निर्देश दिए। साथ ही ग्राम स्तर पर संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में असेसमेंट कर आगामी दो दिन में फीडबैक प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अधिशेष पदों पर विशेष ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि एक पद पर दो चिकित्सक नहीं रहें।

सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे

खींवसर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हों। अस्पतालों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। जिन अस्पतालों के भवन जर्जर हालत में हैं, उनकी मरम्मत करवाई जाए। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आगामी दिनों में हीट-वेव को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रोगी का समुचित इलाज कर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना जिम्मेदारीपूर्ण दायित्व है। इसी भावना को ध्येय में रखना वास्तविक रूप से विश्व स्वास्थ्य दिवस आयोजन की सार्थकता होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के बेसिक पैरामीटर जरूर पूरे हों

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वयं से एक वादा करते हुए संकल्पबद्ध होकर बेहतर कार्य करने की सभी से अपील की। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा वे नियमित रूप से बेसिक पैरामीटर्स की जरूर समीक्षा करें, ताकि किसी भी स्तर पर कोई कमी न रहे। उन्होंने कार्यक्रम में लांच किए गए सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम को काम में लेते हुए प्रतिदिन समीक्षा करने पर भी जोर दिया।

आपातकालीन तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल करें

श्रीमती राठौड़ ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गैर संक्रामक बीमारियों पर विशेष फोकस करने और जीरियाट्रिक केयर पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजन भी सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान, अस्पतालों के नए भवनों के लिए भूमि आवंटन कार्य, टीकाकरण कार्यक्रम, ई-उपकरण, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन, मानव संसाधन के समुचित प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि डर्मेटोलॉजी संस्थान विश्व का दूसरा ऐसा संस्थान है, जहां इस स्तर की उन्नत तकनीक और आधुनिक मशीनों का समावेश किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं न केवल उपचार बल्कि अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

एचपीवी वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक जोगाराम ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने एचपीवी वेक्सीन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए नियमित रूप से स्कूलों में चर्चा कर नजदीकी पीएचसी या अन्य स्वास्थ्य केन्द्र पर लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कायाकल्प कार्यक्रम, गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम पर विचार व्यक्त किए।

दवाओं की आपूर्ति की हो नियमित समीक्षा

निदेशक आरएमएससीएल पुखराज सेन ने कहा कि प्रत्येक रोगी को दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान रखा जाए। दवाओं की मांग और आपूर्ति की नियमित समीक्षा करें। आवश्कता होने पर स्थानीय स्तर पर भी दवा क्रय करने का प्रावधान है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में आने वाले रोगियों को दवाओं की उपलब्धता रहे। उन्होंने ई-उपकरण कार्यक्रम के तहत उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

हाईरिस्क गांवों में हों टीबी उन्मूलन के लिए कैम्प

निदेशक जन-स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने टीबी मुक्त कार्यक्रम के तहत हाईरिस्क गांवों में कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय अभियान में सभी की टीबी के लिए स्क्रीनिंग किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही एमएलसी बनाई जाए।

बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी,निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित डॉ. सुशील परमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

40 हजार रुपये का किया कैरिंग चार्ज वसूल, 3 केन्टर सामान जब्त

जयपुर, (विराट वैभव)। नगर निगम जयपुर आयुक्त श्री ओम कसेरा के निर्देशानुसार एवं पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में मंगलवार को सतर्कता शाखा की द्वारा नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए विद्याधर नगर परशुराम सर्किल पुलिस थाने के पास, स्टेडियम के पास अग्रसैन सर्किल बियानी कॉलेज रोड़, सेन्ट्रल स्पाईन नेशनल हैण्डलूम एवं वीकेआई रोड़ नं. 17 से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 40 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 3 केन्टर सामान जब्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता ने बताया कि नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए विद्याधर नगर परशुराम सर्किल पुलिस थाने के पास, स्टेडियम के पास अग्रसैन सर्किल बियानी कॉलेज रोड़, सेन्ट्रल स्पाईन नेशनल हैण्डलूम एवं वीकेआई रोड़ नं. 17 से अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 3 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 40 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइष करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

खोया-पाया

मेरे आवास सख्या 5/ छ/56 नाहरी का नाका जयपुर का मूल कब्जा पत्र, अदेय प्रमाण पत्र एवं डिक्लरेशन पत्र कहीं खो गया हैं। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें।

मो.- 9252716051.

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर दूरभाष संख्या: 0141-4901853

क्रमांक: 1037 दिनांक: 07/04/2026

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा **आवास संख्या 1/ग/5 जवाहर नगर, जयपुर 263.00 वर्ग गज** का आवंटन श्री सायर मल दुग्गड़ पुत्र श्री मनमल दुग्गड़ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 734 दिनांक 26/03/1981 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 1905 दिनांक 18/08/1981 जारी किया गया था।-उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर नगर में दिनांक 24/06/1988 को करवाया गया। आवंटी श्री सायर मल दुग्गड़ की मृत्यु दिनांक 05/03/2026 को हो जाने के कारण श्रीमती प्रकाश दुग्गड़ पत्नी स्व.श्री सायर मल दुग्गड़ एवं श्री अनुराग दुग्गड़ पुत्र स्व. श्री सायर मल दुग्गड़ के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा हस्तांतरण शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रजिस्टर्ड हकत्याग की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त **आवेदनकर्ता श्रीमती प्रकाश दुग्गड़ पत्नी स्व.श्री सायर मल दुग्गड़ एवं श्री अनुराग दुग्गड़ पुत्र स्व. श्री सायर मल दुग्गड़** के पक्ष में आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक वृत तृतीय, रा.आ.म.जयपुर

जेडीए द्वारा ई-नीलामी के जरिये 4 भूखण्ड़ों का विक्रय

जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयुक्त उत्साह चौधरी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में भव्य ई-नीलामी के अन्तर्गत मंगलवार को सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विहार आवास योजना के दो-दो भूखण्ड़ों का विक्रय किया गया। प्राधिकरण द्वारा बुधवार, 08 अप्रैल को सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना के भू.सं 492, 493, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विहार आवास योजना के भू.सं. 114 व 115 की ई-नीलामी की जाएगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

ई–निविदा सूचना सख्या 01 to 02–26–27 मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक 27.04.2026 को 15.00 बजे तक खुली ई–निविदा आमंत्रित करते है:– **निविदा संख्याः** 01 **कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मंडल इंजीनियर/लाईन, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में 24 माह के लिए नापासर (छोड़कर)– नाथवाणा (छोड़कर) खण्ड पर स्टेशनों, सेक्शन, गैंग एवं समपारों पर पीने के पानी की आपूर्ति करने का कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** Rs. 2586045.44 **धरोहर राशिः** Rs. 51700.00 **निविदा संख्याः** 02 **कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर, सूरतगढ़ के नियंत्रण में बैलास्ट डिपो रामसिंहपुर में आरडीएसओ ट्रेक बैलास्ट स्पेशिफिकेशन आइएस/आरडीएसओ–जी ई/0001:2023 फरवरी–2023 के अनुसार 65 मिमी गेज मशीन द्वारा तोड़ी गयी रोड़ी गई 45500 घनमीटर रोड़ी की सप्लाई करना और उसकी रेलवे वैगनस / होपरस में लदाई का कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** Rs. 93835350.00 **धरोहर राशिः** Rs. 1876700.00 **नोटः**– अन्य शर्ते रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। पत्राक– 128-W/WA/Supply of 45500 Cum/RMSR Depot/26 दिनाक 06.04.2026 499-AJ/26

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

आयुक्त ओम कसेरा ने जनगणना 2027 की तैयारियों के संबंध में ली समीक्षा बैठक

आयुक्त की आमजन से अपील 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक अधिक से अधिक संख्या में स्व-गणना कर राष्ट्रहित के कार्य में करे सहयोग

जयपुर, (विराट वैभव)। नगर निगम आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री ओम कसेरा द्वारा जनगणना 2027 की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को समीक्षा बैठक ली गयी। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानसूचीकरण का कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि 01 मई 2026 से 15 मई 2026 तक CMMS (Census Management and Monitoring System) पोर्टल पर मोबाईल नम्बर से पंजीकृत करके अपनी सूचना दर्ज कर सकते है।

आमजन द्वारा दर्ज की गई सूचना को 16 मई 2026 से 14 जून 2026 के मध्य प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जावेंगा। आमजन द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकार योजना संबंधी नीतिगत निर्णय लिये जाते है।

आयुक्त श्री ओम कसेरा ने आमजन से अपील की है कि 01 मई 2026 से 15 मई 2026 तक अधिक से अधिक संख्या में स्व-गणना कर राष्ट्रहित के कार्य में सहयोग प्रदान करें।

SUPREME HOME LOANS

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
रजि. ऑफिस : दूसरी मंजिल, हर्षा भवन, 13/29, ई-ब्लॉक, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
CIN: U67190DL2014PLC272457; टेलीफोन नंबरः +9111-41323147
ईमेल ; customercare@supremehomeloans.com वेबसाइट: www.supremehomeloans.com

सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शाखा प्राधिकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी का वह शाखा कार्यालय जो **सेकंड फ्लोर, रघुनन्दन टावर, बॉम्बे मोटर चौराहा, जोधपुर, राजस्थान 342003** में स्थित है, 13 जुलाई 2026 को कार्य समय समाप्त होने के बाद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका संचालन पास के ही एक शाखा कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है जो **204, थर्ड फ्लोर, आदिनाथ नगर, नई बस स्टैंड, पाली जिला, राजस्थान 306401** में स्थित है। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप उल्लिखित निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं customercare@supremehomeloans.com. -
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है (www.supremehomeloans.com).

फॉर एंड ओन बेहल्फ़ ऑफ सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
तारीख: 08.04.2026 हस्ताक्षर /- नेहा भाटिया कंपनी सचिव